[अध्यक्ष महोदय]

चाहिये, और यह पार्लियामेंट रहनी चाहिये। हमारे और आप जैसे आते जाते रहेंगे, लेकिन Parliament must have the dignity of its own

---

13.23 hrs.

PERSONAL EXPLANATION BY MEMBER

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) अध्यक्ष जी, मैं आप की इजाजत से एक व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। शिक्षा मन्त्रालय के अनुदान की मांगों पर जब 4 अप्रैल को बहस हो रही थी तो श्री चन्द्र पन ने मेरे नाम का हवाला देकर एक बात कही। उन्होंने कहा, मैं उनके शब्दों को उद्धृत कर रहा हूं :

"You may be knowing that the leaders of the syndicate are taking interest in this University. (Aligarh Muslim University). Shri Piloo Mody has been bestowed the life membership of the Aligarh Muslim University. Mr. Atal Bihari Vajpayee visited the University and had discussion there."

अध्यक्ष महोदय, मैं अभी तक उस विश्व विद्यालय में गया नहीं हूं निकट भविष्य में उस विश्वविद्यालय में मेरा जाने का कोई इरादा नही है। श्री चन्द्रप्पन को सही जानकारी रखनी चाहिये। इस सदन में आकर इस तरह की अनर्गल बातें कहना या तो मुझे बदनाम करने का तरीका है, या मेरी पार्टी को बदनाम करने का तरीका है। किसी प्रेस में यह छपा हुआ नही है। यह बिल्कुल गलत बात है। सी० पी० आई० के मेम्बर इस तरह की अनर्गल बातें कह कर देश के वातावरण को बिगाड़ना चाहते है।

13.25 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS, 1973-74—Contd.

MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND DEPARTMENT OF CULTURE —contd.

MR. SPEAKER: The House will now take up further discussion on the Demands for Grants relating to the Ministry of Education and Social Welfare and the Department of Culture.

Shri Mulki Raj Saini to continue his speech.

श्री मुल्की राज सैनी (देहरादून) : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि सरकार ने शिक्षा के प्रसार के लिये और शिक्षा को गरीबों तक पहुंचाने के लिये कुछ दिशा बदलनी है और उनकी यह योजना प्रशंसनीय है। देश के अन्दर 1971 से राज्य सरकारो को 30,000 टीचर्स, 240 इंसपेक्टर और 1000 वर्किंग टीचर्स दिये गये। इसी तरह से 1972 और 1973 में 90,000 टीचर्स 720 इंसपेक्टर्स और 3,000 वर्किंग टीचर्स दिये गये हैं। जिससे आभास होता है कि 6 से 11 साल तक के बच्चों को प्राइमरी शिक्षा देने की योजना पूरी हो जायगी। यह कार्य प्रशसनीय है।

13.26 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*].

इसी तरीके से पढ लिखे अनएम्प्लायड लोगों को रोजगार देने के लिये 29 करोड रु० बजट में रखा गया है। इसी तरीके से सरकार ने तकनीकी, प्रौद्योगिकी और इजीनियरिंग शिक्षा के वास्ते अलग अलग सस्थान खोल रखे हैं। सवाल यह होता है कि इन सस्थानों में किस के बच्चे पढ सकते हैं ? क्योंकि यह बहुत खर्चीली शिक्षा है इसलिये इनमें किसी गरीब का बच्चा, निम्नतम श्रेणी का बच्चा, मध्यम श्रेणी का बच्चा, हरिजन, आदिवासी और देहात के गरीब तबके के लोग नही जा सकते हैं। इस वास्ते मेरा सुझाव है कि सरकार को यह शिक्षा गरीब के बच्चों तक पहुंचाने के लिये सस्ती करनी चाहिये। आप कहेंगे कि छात्रवृत्तियां हैं। लेकिन वह इतनी कम हैं कि इस मांग को पूरा नहीं करतीं। तो इस तरीके से सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिये।